

अप्रैल में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं राजस्थान से

ऐसा अनुमान है, दो सीटें भाजपा को और एक कांग्रेस को मिलेगी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 जनवरी। राजस्थान से कांग्रेस के लिए एकमात्र राज्यसभा सीट को लेकर हड़बड़ी शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार संसद के ऊपरी सदन में प्रवेश करने के लिए दौड़ में हैं, उनकी सूची लंबी है। उतनी ही लंबी, जितनी इन कांग्रेसी नेताओं की आकांक्षाएं।

अप्रैल 2026 में तीन सीटें खाली होंगी, जिनमें से दो सीटें भाजपा को मिलेंगी, और एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यसभा में अपना स्थान बनाने और अपनी राजनीति दिल्ली शिफ्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है कि राजस्थान में उनके रास्ते बंद हो चुके हैं।

वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाकर उनकी जगह राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनने का सपना देख रहे हैं।

जैसा कि पहले ही रिपोर्ट किया गया है, गहलोत अपनी सभी तैयारियाँ मुंबई से कर रहे हैं, जो देश की वित्तीय राजधानी है।

■ कांग्रेस की सीट के लिए काफी घमासान मचा है तथा सबसे आगे खड़े हैं, पूर्व मु.मंत्री अशोक गहलोत। गहलोत की महत्वाकांक्षा है, वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालें। इसीलिए गहलोत देश की फायनैंशियल राजधानी मुंबई गए हुए हैं, अपनी राज्यसभा सीट का पूरा इंतज़ाम करने।

■ दूसरे सशक्त उम्मीदवार हैं, अभिषेक मनु सिंघवी। जाने माने वकील, जो कांग्रेस के लिए कवच की जिम्मेवारी निभाते हैं, पार्टी व उसके नेताओं के खिलाफ दायर मुकदमों में। दो वर्ष पूर्व वे तेलंगाना से राज्यसभा सदस्य बने, बाई इलैक्शन में। उनका कार्यकाल इस वर्ष पूरा हो रहा है, अतः वे राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनने का प्रयास कर सकते हैं। पर, उनके समक्ष तेलंगाना का विकल्प भी है, क्योंकि तेलंगाना में भी सीटें खाली हो रही हैं। एक पर तेलंगाना के मु.मंत्री अपने नज़दीकी अनिल यादव को लाना चाहते हैं, पर, दूसरी सीट पर अभी तक कोई गंभीर उम्मीदवार नहीं हैं।

■ राजस्थान में कांग्रेस की सीट के लिए तीसरे महत्वपूर्ण उम्मीदवार पवन खेड़ा हैं। पिछली बार भी वे उम्मीदवार थे, पर, हार गए थे और अपनी हार पर उनकी रोचक टिप्पणी थी, “शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी।” इस बार वे उस कमी को पूरा करने के लिए विपश्चना कैम्प में भी गए थे।

■ वरिष्ठ नेता सी.पी. जोशी, कांग्रेस की सीट पर आँख गाड़े बैठे हैं, हालांकि, वे राहुल गांधी को नाराज़ कर चुके हैं, अतः के.सी. वेणुगोपाल के रास्ते से अंदर घुसना चाहते हैं।

■ वैसे पवन गोदारा का नाम भी जोरों से चल रहा है। तर्क है कि जाट को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। अतः दूसरे जाट को राज्यसभा का टिकट देकर, जाटों को थोड़ी सात्वना तो देनी ही चाहिए।

एक और दावेदार हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो राजस्थान से हैं और

राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। दो साल पहले उन्हें तेलंगाना से उपचुनाव में

राज्यसभा के लिए चुना गया था, उस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या लद्दाख में भारतीय सेना को रैस्क्यू मिशन्स में उलझाया जा रहा है

उमलिंग ला पास पर एक यू ट्यूबूर को सेना द्वारा बचाए जाने से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 जनवरी। लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाकों में बचाव अभियानों में भारतीय सेना की भूमिका को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। यह बहस उस वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई है, जिसमें एक मशहूर यूट्यूबर को “उमलिंग ला पास” के पास बचाया जाता हुआ दिखाया गया है। उमलिंग ला दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़कों में से एक है। यह बहस एक्स पर रतन ढिल्लों की पोस्ट से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से सेना अपने मुख्य काम से भटक जाती है, जबकि यह इलाका बहुत संवेदनशील सीमा क्षेत्र है। ढिल्लों ने कहा, ऐसा लगता है कि लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना को अपने असली कर्तव्यों पर ध्यान देने के बजाय, लोगों को बचाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उसकी परेशानियाँ बढ़

■ उमलिंग ला पास विश्व की ऐसी सबसे ऊंची सड़कों में से एक है, जहाँ वाहन चलाया जा सकता है, पर, इसके लिए वाहन चालक में विशेष योग्यता की जरूरत होती है।

■ एक यूजर, रतन ढिल्लों ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में कहा, ऐसे खराब मौसम में इन दुर्गम स्थानों पर जाने की किसी को भी अनुमति क्यों दी जाती है, क्योंकि इन लोगों को बचाने की कवायद में सेना अपने असली मिशन से भटक जाती है।

रही हैं।

इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, “हाल ही का एक उदाहरण एक मशहूर यूट्यूबर का है, जिसे न तो सही ड्राइविंग आती थी और न ही उसे ऊंचाई वाले इलाकों का कोई अनुभव था। उसे कल उमलिंग ला पास पर बचाना पड़ा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर चलाने योग्य पास है। उसने खुद वीडियो में “ब्लैक आइस” का

जिक्र किया है और यह भी कहा है कि वहाँ आसपास कोई और व्यक्ति या वाहन मौजूद नहीं था।”

इस पोस्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आम लोगों, खासकर खराब मौसम के समय, को ऐसे बेहद खतरनाक इलाकों में जाने की इजाजत क्यों दी जाती है।

ढिल्लों ने एक्स पर पूछा, “इससे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘भर्ती प्रक्रिया के हर स्तर पर मिली भगत साबित नहीं हुई’

जयपुर, 8 जनवरी। एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गुरुवार को चयनित अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपना पक्ष रखा गया। वहीं, अदालत ने मामले में अब 12 दिसंबर को सुनवाई तय की है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस

■ एसआई भर्ती मामले में चयनित अभ्यर्थियों के अधिवक्ता ने पक्ष रखा।

संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने अदालत को बताया कि मामले में एसओजी की रिपोर्ट नकल कराने वाली गैंग के सदस्यों का इतिहास बताती है, न कि इस भर्ती के पेपर लीक को। एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में फ्लू के मामलों में तेजी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 जनवरी। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली-एनसीआर में फ्लू जैसे लक्षणों और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में साफ बढ़ोतरी देखी जा रही है। मरीजों में खांसी-जुकाम, तेज बुखार, बदन दर्द, छाती में जकड़न, सिरदर्द और कुछ मामलों में उल्टी जैसे लक्षण सामने आ रहे हैं।

चिंता की बात सिर्फ मरीजों की संख्या नहीं है, बल्कि बीमारी का तरीका भी है। कई लोग उम्मीद से ज्यादा समय में ठीक हो रहे हैं, जबकि कुछ की, थोड़ी राहत के बाद, फिर से तबीयत बिगड़ रही

■ सूत्रों ने बताया कि लोगों में खांसी, जुकाम, तेज बुखार, बदन दर्द, सीने में जकड़न, सिरदर्द और उल्टी की शिकायत बढ़ गई है। कुछ मरीजों में तो एच3 एन3 वायरस भी पाया गया है।

है। डॉक्टरों का कहना है कि यह सर्दियों में होने वाले मौसमी संक्रमण जैसा ही है, लेकिन लक्षणों की तीव्रता, खासकर अचानक तेज बुखार और लंबे समय तक रहने वाली खांसी, लोगों को डरा रही है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका हमेशा वेनेज़ुएला के ऑयल के निर्यात पर नियंत्रण रखेगा?

राष्ट्रपति ट्रंप व अमेरिका के एनर्जी सैक्रेटरी क्रिस राइट ने अमेरिका का यह दीर्घकालीन प्लान उजागर किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 जनवरी। ट्रम्प प्रशासन वेनेज़ुएला के तेल की भविष्य में होने वाली बिक्री पर नियंत्रण करने और उसकी आय को अमेरिकी खातों में रखने की योजना बना रहा है। ऊर्जा सचिव क्रिस राइट ने यह जानकारी दी, जो अब तक की वॉशिंगटन की रणनीति पर सबसे स्पष्ट बयान है। यह रणनीति वेनेज़ुएला के कच्चे तेल को बाज़ार में लाने और इसके सबसे मूल्यवान संसाधन पर नियंत्रण रखने के लिए है।

राइट, जो बुधवार को मायामी गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक. के सम्मेलन में बोल रहे थे, ने कहा कि शुरुआत में यह तेल वेनेज़ुएला के स्टोर किए गए तेल से आएगा, जो अमेरिकी नाकेबंदी के कारण भरने लगा है और कुछ उत्पादन को ऑफ़लाइन करने की धमकी दे रहा है।

राइट ने कहा, “हम बस उस तेल को फिर से प्राप्त करेंगे और बेचेंगे, हम वेनेज़ुएला से आने वाले तेल को मार्केट करेंगे, पहले यह बैक-अप स्टोर किया हुआ तेल और फिर अनिश्चितकालीन

■ ट्रंप के अनुसार, पहले अमेरिका वेनेज़ुएला के पास जमा उस 50 मिलियन बैरल ऑयल, जिसकी कीमत 2.8 बिलियन डॉलर आंकी जाती है और जो वेनेज़ुएला के स्टोरेज में रखा है और जिसकी अमेरिका के “ब्लॉकेड” के कारण बिक्री नहीं हो सकी थी, को बेचेगा।

■ और इसके बाद जो भी ऑयल वेनेज़ुएला की ऑयल फ़ील्ड्स से निकलेगा, उसका बेचान भी अमेरिका ही करेगा।

■ इसके अलावा अगले सप्ताह, अमेरिका की सीनेट में एक विधेयक पेश होगा, जिसके अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार मिलेगा, मॉस्को से व्यापारिक संबंध रखने वाले देश, जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील आदि, पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगा सकने का, अगर ये देश रूस से ऑयल खरीदते रहे।

■ यह 500 प्रतिशत टैरिफ इसलिए लगाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की दृष्टि में ये देश रूस से ऑयल खरीद कर रूस के हाथ मजबूत कर रहे हैं, यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए।

रूप से हम वेनज़ुएला से जो उत्पादन होगा, उसे बेचेंगे।”

यह योजना तब सामने आई है, जब (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लगातार नौवाँ बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी निर्मला सीतारमण

सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने अब तक के अपने सभी बजट एक ही प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में पेश किए हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 जनवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार 1 फरवरी को 2026-27 का केन्द्रीय बजट पेश करेंगी, जो कि रविवार का दिन होगा।

इससे पहले, बजट शनिवार को तो पेश किया जाता रहा है, लेकिन कभी भी रविवार को नहीं पेश किया गया। संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का सम्बोधन 28 जनवरी को होगा, जो बजट सत्र की शुरुआत होगी। आर्थिक सर्वेक्षण (इकॉनॉमिक सर्वे) 29 जनवरी को पेश किया जाएगा।

हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, जिनमें वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक सनसनीखेज सैन्य ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया, को देखते हुए, इस सत्र में विवाद होने की संभावना है।

■ इससे पहले, हालांकि, मोरारजी देसाई 10 बजट पेश कर चुके हैं, पर, उन्होंने दो अलग-अलग दौर में बजट पेश किए थे।

■ इस बार के बजट की एक खास बात यह है कि बजट एक फरवरी, रविवार को पेश होगा, आमतौर पर रविवार को संसद में अवकाश रहता है।

■ लेकिन हालिया अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की वजह से संसद में विपक्ष के सवाल सरकार को असहज कर सकते हैं। वेनेज़ुएला घटनाक्रम पर भारत सरकार की हल्की प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है।

■ इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में ट्रंप की अपमानजनक टिप्पणियों व धमकियों के मद्देनजर भी विपक्ष सरकार की घेराबंदी के लिए तैयार है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेता सरकार से वेनेज़ुएला में हुए घटनाक्रमों पर भारत

सरकार की मूक प्रतिक्रिया पर सवाल उठाने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही हाल

ही में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक और उकसाने वाली टिप्पणियों पर भी विपक्ष सवाल करेगा। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते निचले स्तर पर हैं, और वॉशिंगटन रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल लागू करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य भारत, चीन तथा ब्राज़ील सहित, उन देशों को दंडित करना है, जो रूस का तेल खरीदते हैं और “पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन प्रदान करते हैं”। इस बिल में एक प्रावधान है, जिसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों पर 500 प्रतिशत तक शुल्क बढ़ा सकता है, जो रूस का तेल खरीदते हैं। प्रधानमंत्री मोदी या उनके किसी वरिष्ठ मंत्री ने इन घटनाक्रमों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विपक्षी नेता इन और अन्य संबंधित मुद्दों पर सरकार को घेरने के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भर्ती परीक्षा में नकल का ईनामी आरोपी गिरफ्तार

जयपुर, 8 जनवरी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) राजस्थान ने भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दस हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने

■ आरोपी खुद गैंग से मिली भगत कर ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर रहा था।

बताया कि राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के दौरान नकल कराने की शिकायत मिली थी। तकनीकी जांच में सामने आया कि तुलछाराम कलेर और पावर कलेर गैंग द्वारा परीक्षा केन्द्र के आसपास रहकर अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनाना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। –रोबिन शर्मा

युवाओं के सपनों को उड़ान देता डिजिफ़ैस्ट ग्लोबल समिट

राजस्थान के सूचना एवं प्रौद्यौगिकी विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट इस मायने में महत्वपूर्ण आयोजन हो जाता है कि डिजिटल क्रांति और एआई के युग में समय के साथ चलतू हुए युवा सपनों की उड़ान को बेहतर अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराये है। इस दौरान जहां जयपुर में बड़ा डेटा सेंटर स्थापना की राह प्रशस्त हुई है वहीं 200 करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाएं उभर कर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच का ही परिणाम रहा कि ग्लोबल समिट मात्र औपचारिकता बनकर रहने के स्थान पर ठोस परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा है। युवाओं और तकनीक के प्रति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आयोजन के पहले से वे इसकी सफलता को लेकर गंभीर रहे और समय समय पर आयोजन तैयारियों की ना केवल समीक्षा की अपितु आयोजन को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोजन देश-दुनिया के सामने राजस्थान को आईटी सेक्टर का भी निवेश का बड़ा केन्द्र बनाने की दिशा में अग्रगामी कदम सिद्ध हुआ है साथ ही युवाओं, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप के लिए बेहतर अवसर सिद्ध हुआ। आयोजन के माध्यम से यह भी समझने का प्रयास किया गया कि डिजिटल युग में डेटा संपदा का स्थान लेता जा रहा है। आज डेटा का जमाना आ गया है और डेटा विश्लेषण से भावी का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। आयोजन की सफलता को इसी से आंका जा सकता है कि केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राजस्थान को टेक्नोलॉजी, एआई कर बड़ा हब बनाने का रोडमैप तैयार किया है। देश के 10 लाख युवाओं को एआई स्किलिंग ट्रेनिंग देने की शुरुआत भी राजस्थान की राजधानी जयपुर से ही की गई। गूगल के साथ जो एमओयू संपन्न हुआ है उसके दूरगामी लाभ प्रदेश और प्रदेश के युवाओं, एन्टरप्रेन्योर, एमएसइएमई सहित वासियों को मिलने वाला है। एमाओयू के अनुसार गूगल की एक टीम राजस्थान में सक्रिय रहकर कार्य करेगी। इस आयोजन का एक और बड़ा सार्थक परिणाम यह भी सामने आने वाला है कि सरकारी अधिकारियों से लेकर छात्रों, संस्थानों, स्टार्टअप, आदि-आदि के लिए लार्ज स्केल पर रिकालिंग प्रशिक्षण आदि की बेहतरीन विश्वस्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी।

राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वो. श्रीनिवास ने सही ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार एंटरप्रेन्योरशिप में एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और गुड गवर्नेंस में एआई के सटीक उपयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने एआई-एमएल पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट एलएमएस, राजस्थान एबीजीसी-एक्सआर पोर्टल तथा राजस्थान एआई पोर्टल को लॉन्च किया है। तीन दिन चले राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट में निवेशक फाउंडर बैठकों, पिच सत्रों और बैठकों के माध्यम से 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावनाएं बनी। राजस्थान सरकार ने भी पहल करते हुए स्टार्टअप में सह-निवेश करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की। समिट के माध्यम से 100 से अधिक स्टार्टअप को मेंटरशिप कार्यक्रमों में शामिल किया गया। 8,867 से अधिक प्रतिभागियों के साथ कॉमिककॉन ने राजस्थान को रचनात्मक उद्योगों, गेमिंग और डिजिटल स्टोरीटेलिंग के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित किया।

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एआई और डिजिटल लिट्रेसी पर जोर देने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान की ही बात करें तो प्रदेश में साढ़े छह करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ता है और एक मोटे अनुमान के अनुसार 81 हजार करोड़ रु. की लेनदेन प्रति माह यूपीआई प्लेटफार्म के माध्यम से हो रहा है। साइबर अपराधियों के लाख प्रयासों के बावजूद हाँसले बुलंद है। ऐसे लिट्रेसी समय की मांग व आवश्यकता है। कहने का अर्थ यह है कि डिजिटल क्रांति और एआई दुधारी तलवार का काम करती है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखते हुए, ही सरकार गंभीर प्रयास करने जा रही है। एआई-एमएल पॉलिसी निश्चित रुप से ई गवर्नेंस से लेकर रोजगार के अवसरों तक उपयोगी सिद्ध होगी।

आयोजन की खास बात यह है कि डिजिटल युग और एआई से जुड़े सभी संभावित क्षेत्रों के विशेषज्ञों और लाभार्थियों को साझा मंच उपलब्ध कराया गया और इसका परिणाम यह रहा कि अनुभवों को साझा करने और जिज्ञासाओं के निराकरण का अवसर प्राप्त हो सका। इस तरह के आयोजनों निश्चित रुप से दीर्घकालीन परिणाम देने वाले होते हैं और भविष्य की भूमिका भी लिखते हैं। निश्चित रुप से यह आयोजन युवाओं, स्टार्ट अप्स, उद्यमियों, एस्पएमई सेक्टर आदि के साथ ही भावी पीढ़ी यानी कि विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध तो हुआ ही है क्योंकि निवेश और निर्णयों को धरातल पर आने से राजस्थान और यहां के युवाओं को सुनहरी राह मिल सकेगी।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल शुक्रवार 9 जनवरी, 2026

माघ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन 1:41 तक, शोभन योग सायं 4:55 तक, विष्टि करण सायं 7:45 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-धनु, बुध-धनु, गुरू-मिथुन, शुक्र-धनु, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रवियोग दिन 1:41 तक है। भद्रा प्रातः 7:06 से सायं 7:45 तक रहेगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:40 तक, लाभ-अमृत 8:40 से 11:16 तक, शुभ 12:34 से 1:52 तक, 7:21 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:21, सूर्यास्त 5:46

 मेघ परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लगेंगे। आज अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। चलते कार्यों का विस्तार होगा।	 सिंह आर्थिक मामलों में बनाए रखना ठीक रहेगा। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।	 धनु यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।
 वृष व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	 कन्या आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी।	 मकर नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटकें हूए कार्य बनने लगेंगे। आज धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक पारिवारिक खर्चों में नियंत्रण रखें।
 मिथुन घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।	 तुला व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागवैद्ध रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।	 कुंभ चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आज नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। यात्रा में दुर्घटना का भय है।
 कर्क परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।	 वृश्चिक आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।	 मीन परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

संपादकीय

सरकार की जनहितकारी सोच से 12 किमी का फासला घटकर 2 किमी हुआ

भौगोलिक दूरी कम हुई, सरकार और पब्लिक साथ कदमताल कर विकास के पथ पर अग्रसर



नवधा परदेशी

जनजाति अंचल केवल भौगोलिक इकाई नहीं होता, वह अपने भीतर संघर्ष, धैर्य और सदियों पुरानी जीवनशैली को समेटे रहता है। राजस्थान का जनजाति जिला प्रतापगढ़ भी ऐसा ही अंचल है। जहाँ पहाड़, नाले, नदी और कच्चे रास्ते लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ विकास की राहें केवल योजनाओं से नहीं बल्कि ज़मीन पर उठते छोटे-छोटे प्रयासों से बनती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। सरकार यह जानती है कि जनजाति अंचल में विकास का अर्थ केवल इमारतें या सड़कें नहीं होता, बल्कि यह जीवन को सरल बनाने का प्रयास होता है। इसी सोच का परिणाम

प्रतापगढ़ जिले की विषम भौगोलिक संरचना वर्षों से यहाँ के निवासियों के लिए चुनौती रही है। जिले में माण्डवी पारसोला रोड से सखीखेड़ा सड़क पर सूकली नदी पर 4 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण किया गया है । पहले लोगों को पारसोला, साबला, डूंगरपुर या आसपुर पहुँचने के लिए 10-12 किलोमीटर का लंबा, घुमावदार और थकाने वाला मार्ग तय करना पड़ता था। यह दूरी केवल किलोमीटर की नहीं थी बल्कि समय, श्रम और अवसरों की भी दूरी थी। ठाम पंचायत गाडरियावास, कैसरपुरा, बिजाणिया और जवाहरनगर के गाँवों व फलों के लोगों के लिए यह पुलिया वरदान साबित हुई है। अब वही रास्ता मात्र 2 किलोमीटर में सिमट गया है। जो यात्रा पहले मजबूरी थी, अब सुविधा बन गई है।

पुलिया का प्रभाव केवल



आवागमन तक सीमित नहीं है। यह किसानों के लिए अपने उत्पाद को बाज़ार तक समय पर पहुँचाने का माध्यम है, विद्यार्थियों के लिए स्कूल-कॉलेज तक आसान पहुँच का रास्ता है और बीमारों के लिए अस्पताल तक शीघ्र पहुँचने के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए यह सुविधा सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है तो युवाओं के लिए रोजगार और भविष्य की संभावनाओं से। यह केवल एक पुलिया की कहानी है, जनजाति क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा

किया गया हर एक विकास कार्य सफलता और विकास के अनेखी कहानी अपने में समेटे हुए है। सूकली नदी पर बनी यह पुलिया उसी सोच की मिसाल है, जहाँ सरकार की संवेदनशीलता और ज़मीनी ज़रूरतें एक-दूसरे से जुड़ती हैं। यह पुलिया बताती है कि जब नीतियाँ जनजाति जीवन की धरातल की वास्तविकताओं को समझकर बनाई जाती हैं, तब ख़ाब जैसा परिवर्तन केवल साकार ही नहीं देता, दिलों में समा भी होता है। राज्य सरकार के द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए किए गए विकास कार्य एवं लिए गए नीतिगत जनकल्याणकारी निर्णय जनजाति अंचल में आने वाले वर्षों के लिए न केवल विकास, सुविधा और विश्वास की नींव मजबूत कर रहे हैं बल्कि समावेशी सुप्रशासन और सरकार और जन के बीच के विश्वास और वादों को निभाने की नई इबारत लिख रहे हैं जो पुल का इमारत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।

—नवधा परदेशी,
एपीआरओ, बांसवाड़ा

शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्ते बनाम आवारा मानव तंत्र

का है।

1. पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा का संतुलन

सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों का प्रबंधन पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत होना चाहिए। कैपस में कुत्तों के लिए विशेष समितियाँ इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वे मूक प्राणी हैं, उनके व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और वे रबीज जैसी घातक बीमारियों के वाहक हो सकते हैं। प्रशासन यहाँ सार्वजनिक सुरक्षा के तर्क को प्राथमिकता देता है, जो कि सही भी है। लेकिन क्या वही सुरक्षा का तर्क तब लागू नहीं होता जब बाहरी राजनीतिक तत्व कैपस में घुसकर छात्रों को डराते-धमकाते हैं या शैक्षणिक माहौल को दूषित करते हैं?

2. “अवांछित मानवीय हस्तक्षेप” की जटिलता

कुत्तों को हटाना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन बाहरी व्यक्तियों या ‘राजनीतिक तत्वों’ को रोकना एक जटिल कानूनी और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है।

संवैधानिक अधिकार बनाम संस्थान के नियम: भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत निर्बाध आवाजाही की स्वतंत्रता देता है। लेकिन शिक्षण संस्थान ‘निष्पक्ष क्षेत्र’

की श्रेणी में आते हैं। प्रशासन के पास यह अधिकार है कि वह बिना अनुमति प्रवेश को अनाधिकार प्रवेश माने।

3. प्रोक्टोरियल बोर्ड की भूमिका: हर विश्वविद्यालय में एक शक्तिशाली प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है। इस बोर्ड का प्राथमिक कर्तव्य अनुशासन बनाए रखना और बाहरी तत्वों की पहचान करना है। यदि गेट पर आई-कार्ड चेकिंग अनिवार्य हो और सीसीटीवी का प्रभावी उपयोग किया जाए, तो बाहरी हस्तक्षेप को शून्य किया जा । यह तर्क सटीक है कि इसके लिए किसी नए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मौजूदा नियमों को लागू करने की इच्छाशक्ति चाहिए। समस्या यहाँ आती है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अक्सर राजनीतिक दबाव में होता है। स्थानीय नेता, छात्र संगठनों के पूर्व नेता (जो अब छात्र नहीं हैं) और अन्य बाहरी तत्व अक्सर वोट बैंक या स्थानीय प्रभाव के कारण कैपस में पैठ बनाए रखते हैं। जब प्रशासन अपने ही बनाए नियमों को लागू करने में विफल रहता है, तो यह आवारा मानवीय तंत्र का रूप ले लेता है, जो आवारा कुत्तों से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि यह सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण होता है।

4. शैक्षणिक वातावरण बनाम राजनीतिक अड्डा

एक विश्वविद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य शोध और शिक्षण है। कैपस केवल छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित अभयारण्य होना चाहिए यदि आवारा कुत्तों को छात्रों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, तो कैपस में अशांति फैलाने वाले, धरना-प्रदर्शन करने वाले बाहरी तत्वों को अवांछित क्यों नहीं माना जाता? बाहरी हस्तक्षेप न केवल पड़ाई को प्रभावित करता है, बल्कि यह मेधावी छात्रों के मन में असुरक्षा की भावना भी पैदा करता है। केरल का भावना उच्च न्यायालयों के फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों को सीमित किया जाना चाहिए ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता बनी रहे।

5. समाधान और मार्ग

इस समस्या के समाधान के लिए डॉंग मैनेजमेंट की तर्ज पर विजिटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है:

कठोर प्रवेश नीति: गेट पर डिजिटल आई-कार्ड चेकिंग और बायोमेट्रिक एंट्री को बढ़ावा देना।

राजनीतिक अलगाव: छात्र राजनीति और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना।

बाप तहसील के मोटाई गांव में बिना मान्यता एक घर में चल रहा निजी स्कूल

शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कार्यवाही, ग्रामीणों में रोष

बाप, (निसं)। फलोदी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आकर बिना मान्यता प्राप्त अवैध रूप से स्कूल खोलकर छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब छात्र स्कूल से टीसी मांगते हैं, तो उन्हें टीसी नहीं दी जाती है, जिससे उनके भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि मोटाई गांव में एक घर में अवैध रूप बिना मान्यता प्राप्त से चैंपियन पब्लिक स्कूल संचालित है, लेकिन फिर भी स्कूल बंद करवाने में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

■ जब छात्र स्कूल से टीसी मांगते हैं, तो उन्हें टीसी नहीं दी जाती है

चैंपियन पब्लिक स्कूल संचालित है, लेकिन फिर भी स्कूल बंद करने की जहमत नहीं उठाई जा रही है। जानकारी के अनुसार बिना मान्यता के मोटाई में चैंपियन पब्लिक स्कूल संचालन की शिकायतें लंबे समय से की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि चैंपियन पब्लिक स्कूल

संचालन कर्ता जांच या निरीक्षण करने आने वाले अधिकारियों की आंख में धूल झाँकते हुए बताता है कि वह तो कॉचिंग सेंटर चला रहा है। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि वह बिना मान्यता स्कूल संचालित कर भोले-भाले ग्रामीणों को ठगते हुए उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शिकायत करने पर संचालक ग्रामीणों को धमकाता है। ग्रामीण रामतन विश्नोई सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि चैंपियन पब्लिक स्कूल बिना मान्यता से अवैध रूप से संचालित करने की शिकायतें

जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों से करते आ रहे हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं की जा रही। हिंगलाजदान चारण, सीबीईओ बाप का कहना है कि इसकी जांच कर उच्चाधिकारियों को भेज दी है। इस पर दो साल पहले एफआईआर भी दर्ज हुई थी। वह भी उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट में बता दिया है। कार्यवाही उच्चाधिकारी ही करेंगे। पूर्णराम, देव, प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी फलोदी के अनुसार शिकायत आई है, जांच करवाएँ। अभी मैं बाहर हूँ।

रिटायर लड़ाकू विमान मिग-21 बच्चों और युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा

बीकानेर, (निसं)। यहां 2025 में नाल बेस से भारतीय वायुसेना से रिटायर हुआ लड़ाकू विमान मिग-21 अब स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए सेना में जाने की प्रेरणा बनेगा। इसका एयर फ्रेम श्रीद्वारगढ़ तहसील के बिगाबास रामसरा गांव के कैप्टन चंद्र चौधरी राजकीय सीनियर सेकंडरी स्कूल में रखा जाएगा। प्रदेश में सैनिक स्कूल के बाद यह पहला अवसर होगा, जब एक लड़ाकू विमान का एयर फ्रेम शिक्षा विभाग के किसी सरकारी स्कूल सेना में रखा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने वॉर ट्रॉफी के रूप में इसकी मंजूरी दे दी है। शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट के सीताराम सियाग ने

■ रिटायर लड़ाकू विमान मिग-21 का एयर फ्रेम बिगाबास के सरकारी स्कूल में रखा जाएगा

बताया कि वायु मुख्यालय ने स्कूल

प्रिंसिपल को मेल करके इसकी सूचना दी है। यह एयर फ्रेम बच्चों की शिक्षा के उद्देश्य से दिया जा रहा है। बच्चे मिग-21 के 62 साल की शौर्य गाथा से परिचित हो सकेंगे। युद्धों के दौरान इस विमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की याद में मिलने वाला यह चौथा वॉर

मेमोरियल होगा। सियाग ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुनयाम मेघवाल के प्रयास रहे हैं। बिगाबास रामसरा के सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के पास मंगलवार को एयर हैडक्वार्टर से मेल आया था, जिसकी कॉपी उन्होंने मुझे दी है। मिग-21 के आने से बच्चों को वायु सेना के प्रति रुझान बढ़ेगा।

राज्य में हत्या प्रकरणों में 2 5 व लूट में 5 0 प्रतिशत कमी आई- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने “विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था” विषय पर पुलिस सम्मेलन को संबोधित किया

जयपुर, 8 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सुदृढ़ कानून व्यवस्था की निर्णायक भूमिका है। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता में त्वरित न्याय की अवधारणा से लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है।

गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में ‘विकसित भारत में पुलिस

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को अपने कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने चाहिए।**

व्यवस्था’ विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023 के मुकाबले अपराधों में 15 प्रतिशत, हत्या के प्रकरणों में 25 प्रतिशत, लूट के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, महिला अत्याचार में 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार में 28 प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण के नवाचारों ने प्रदेश को नई



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में “विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था” विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

पहचान दिलाई है और भारत सरकार के उपक्रम “क्षमता संवर्धन आयोग” द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा इन पर पूरी तरह अंकुश लगाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रही है और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग खुफिया सूचनाओं

के विश्लेषण में किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण के महत्व को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को अपने कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने चाहिए। 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले पुलिस अधिकारियों को एक-एक पुलिस स्टेशन को गोद लेना चाहिए।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदूम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने कहा

कि प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग के लिए समर्पित भाव से कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ई-विजिटर्स पोर्टल एवं ई-जोरी एफआईआर का शुभारम्भ एवं राजस्थान पुलिस प्राथमिकता-2026 पुस्तिका का विमोचन किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी.

श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी संजीव कुमार नर्जी सहित, पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

दिल्ली में फ्लू ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
कुछ मरीजों में इन्फ्लुएंजा, जिसमें एच3एन2 भी शामिल है, पाया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि एक साथ कई तरह के श्वसन वायरस और यहां तक कि बाद में होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण भी फैल रहे हो सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह फ्लू क्यों फैल रहा है और शुरुआती दौर में सही कदम उठाने से इसकी गंभीरता और फैलाव दोनों को कम किया जा सकता है।

मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका में संक्रामक रोग विभाग की प्रमुख और

सलाहकार डॉ. अंकिता बैद्य का कहना है, “यह अभी की बात नहीं है, लगभग एक महीने से चल रहा है। फ्लू के बहुत मामले सामने आ रहे हैं और सांस से जुड़ी कई बीमारियां देखी जा रही हैं। यह खासकर यात्रा करने वाले लोगों में ज्यादा है और सभी उम्र के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।”

फोर्टिस एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. अवि कुमार का भी कहना है कि कुछ मामलों में एच3एन2 जरूर है, लेकिन वही अकेला कारण नहीं है।

सरमथुरा में खनन ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
विभाग का दल मौके पर पहुंचा। अवैध खनन रोकने के प्रयास के दौरान वनरक्षक जितेन्द्र सिंह के बाएं पैर पर ट्रैक्टर का टायर चढ़ गया।

इस घटना से वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। ट्रैक्टर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अन्य दल मौके पर पहुंचा। घायल जितेन्द्र सिंह को तत्काल

सरमथुरा अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें करौली रेफर किया गया और फिर जयपुर भेजा गया। विभाग का एक दल उनके साथ जयपुर गया है। वनरक्षक जितेन्द्र सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि घायल वनरक्षक के होश में आने के बाद ही घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। यह घटना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई है।

भर्ती परीक्षा में ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
जरिए नकल कराई जा रही थी। इस संबंध में एसओजी थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि फेरिश कुमार स्वयं अस्थायी था और गैर से मिलीगंगा कर ब्यूट्राल के माध्यम से नकल कर रहा था। मामला

दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया था। जांच पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। एसओजी ने आरोपी फेरिश कुमार (26) निवासी कालू जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अप्रैल में राज्यसभा ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
सीट का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। सिंघवी एक वकील हैं और कांग्रेस नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाल रहे हैं। तेलंगाना से दो सीटें खाली हो रही हैं। रिटायर होने वाले दूसरे व्यक्ति मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी अनिल यादव हैं, तो वे वहां से लौट सकते हैं या राजस्थान से आ सकते हैं।

एक और प्रमुख दावेदार पवन खेड़ा हैं, जो एआईसीसी मोडिया चेयरमैन हैं और जिन्हें अशोक गहलोत का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इस बार गहलोत खुद को ही प्राथमिकता दे रहे हैं।

पिछली बार खेड़ा हार गए थे और तब उन्होंने विनम्रता से कहा था कि, “मेरी तत्पस्था में ही कोई कमी रह गई होगी।” इस बार अपनी तत्पस्था के तहत विपश्यना पर गए थे, हाल ही में लौटे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यही उनका काम बना देगी।

नीरज डांगी राजस्थान से रिटायर हो रहे हैं। लोकप्रियता से दूर तथा शांत रहने वाले डांगी अशोक गहलोत की पसंद थे, लेकिन यह संभावना कम है

कि उन्हें फिर से मौका मिलेगा, फिर भी एक प्रयास में कोई हर्ज नहीं है।

वरिष्ठ नेता सी. पी. जोशी भी काफी समय से दिल्ली में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से रिश्ते खराब होने के बाद, अब वे के. सी. वेणुगोपाल के जरिए प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें राहुल गांधी का प्रॉक्सी माना जाता है।

पवन गोदारा, एक स्थानीय जाट नेता हैं, और यदि पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा को हटایा जाता है, तो एक जाट को राज्यसभा में समायाोजित किया जा सकता है।

हालांकि राज्यसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि राहुल गांधी की “जय जगत” कोर टीम का प्रत्येक सदस्य राज्यसभा के लिए जोर लगा रहा है, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी का समर्थन है और राहुल उनकी बात सुनते हैं।

प्रवीण चक्रवर्ती और सचिन वर राजस्थान से जोर लगा रहे हैं, मीना कश्यप मध्य प्रदेश से, और अन्य कई लोग भी इस दौड़ में हैं।

डिमांड और सपनाई के बीच बड़ा अंतर है और मुकाबला आने वाले हफ्तों में और भी दिलचस्प हो सकता है!!

ममता अपने ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
दफ्तर से चुनावी रणनीति और दूसरी चीजों से जुड़ा डेटा ले जा रही थी, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। यह स्पष्ट रूप से एक राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा अपनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके चल रही जांच में रूकावट डालना था। ई.डी. ने बाद में जोर देकर कहा कि ममता बनर्जी के आने से पहले जांच बिल्कुल ठीक और पेशेवर तरीके से चल रही थी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंची, अफरा-तफरी मच गई और जांच से जुड़े अहम सबूत ईडी अधिकारियों के सामने ही वहां से हटा लिए गए। अब देखना यह है कि ईडी और केन्द्र सरकार इस स्थिति पर

लगातार नौवाँ बजट ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
लिए संयुक्त रणनीतियाँ तैयार कर सकते हैं। कैबिनेट मेटेटी आन पॉलियामेंटी ऑफेयर्स की बुधवार की बैठक में संसद के कैलेंडर की अंतिम रूप दिया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कैलेंडर के अनुसार, बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित होगा: पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल

क्या लद्दाख में ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
एक गंभीर सवाल पैदा होता है कि ऐसे यूट्यूबर्स को इन्हीं जोंखिम भरी और खतरनाक जगहों पर जाने की अनुमति आखिर दी हो क्यों जाती है, वह भी खतरनाक मौसम के दौरान?” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बार-बार ऐसे बचाव

अभियानों से सशस्त्र बलों पर बेवजह दबाव पड़ सकता है। “इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए और अत्यधिक जोंखिम वाले मौसम में ऐसी मंजूरियों को सख्ती से रोक देना चाहिए, ताकि जान-माल का नुकसान न हो और हमारी सशस्त्र सेनाएं अनिवार्यक रूप से परेशान न हों।”

वांगचुक केस में बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, वांगचुक के उस भाषण को दबा दिया गया जिसमें उन्होंने शांति की अपील की थी

- वांगचुक के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंमो ने दायर की है।**

कथित रूप से हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद 26 सितंबर, 2025 को पारित हिरासत आदेश को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिब्बल ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश दुर्भावना से प्रेरित था और अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुख्य रूप से बंदी प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए चार वीडियो पर आधारित था, जिनकी तारीखें 10 सितंबर, 11 सितंबर और 24 सितंबर थीं।

हालांकि, 29 सितंबर को हिरासत के कारणों की जानकारी दी गई थी,

बंगलादेश ने भारत में वीज़ा अनुभाग बंद किया

ढाका, 08 जनवरी। बंगलादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत में अपने तीन मिशनों के वीज़ा अनुभाग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

तौहीद हुसैन ने मीडिया से कहा, “मैंने अपने तीन मिशनों से कहा है कि वे फिलहाल अपने वीज़ा अनुभाग बंद रखें। यह सुरक्षा का मामला है।” उन्होंने हालांकि मिशनों के नाम नहीं

- बंगलादेश के अनुसार यह सुरक्षा के कारण किया गया है।**

बताए, लेकिन यूएनबी के अनुसार, बंगलादेश ने नयी दिल्ली में बंगलादेश उच्चायोग, कोलकाता में उप उच्चायोग और अगरतला में सहायक उच्चायोग के वीज़ा अनुभाग बंद कर दिए हैं, जबकि चेन्नई और मुंबई में बंगलादेश मिशनों के वीज़ा अनुभाग कार्यरत हैं।

ऑक्स्बर्व बंगलादेश के अनुसार, कोलकाता उप उच्चायोग में वीज़ा सेवाओं का निलंबन बुधवार से प्रभावी हुआ। इस फैसले के तहत भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीज़ा सेवाएं, वाणिज्यिक और वर्क वीज़ा को छोड़कर रोक दी गई हैं। वाणिज्यिक और वर्क वीज़ा को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए वाणिज्य दूतावास और वीज़ा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।

भारत ने रुसी तेल की खरीद में चुपचाप कमी की

इसकी भरपाई के लिए परमाणु सहयोग में भारी बढ़ोतरी की संभावना है

नयी दिल्ली, 08 जनवरी। पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी के मद्देनजर, भारतीय कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम कर दिया है या पूरी तरह से रोक दिया है। भारत ने हालांकि आधिकारिक रूप से कहा है कि उसे किसी भी ख़ोत से कच्चे तेल की खरीद करने का अधिकार है, लेकिन उसने चुपचाप रूस से खरीद को कम कर दिया है, जबकि अमेरिका

अमेरिका 6 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग हुआ

वाशिंगटन, 08 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए देश को 66 वैश्विक संगठनों से अलग करने की घोषणा की है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकायों सहित, इन 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोगों से अब अमेरिका का कोई वास्ता नहीं है। आदेश के अनुसार, ये समूह अब अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की सेवा नहीं करते हैं। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प का रुख बेहद स्पष्ट है कि इन संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय जगत की मेहतान की कमाई भेजना अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि

तुर्कमान गेट मस्जिद के पास पथराव में 3 0 आरोपियों की पहचान

तुर्कमान गेट के पास फैज़ ए- इलाही मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने गई नगर निगम टीम पर स्थानीय लोगों ने पत्थर बरसाए थे

- इस मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से भी पूछताछ करेगी। आरोप है कि हिंसा शुरु होने से पहले वे वहीं थे।**

फिर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने तक की बातें शामिल हैं। पुलिसकर्मों स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश रहे थे कि यह तोड़फोड़ अभियान सिर्फ अवैध निर्माणों और अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीन को खाली कराने तक सीमित है और पास की मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। एफआईआर के अनुसार, करीब 12:40 बजे, जब पुलिसकर्मियों ने इलाके में बैरिकेडिंग शुरू की, ठीक उसी समय 30-35 लोगों का एक समूह मौके पर एकत्र हो गया और नारे लगाने लगा तथा पुलिस को नाकाबंदी करने से रोकने लगा।

उपद्रवी ट्रंपों से कहा गया कि वे मौके पर इकट्ठा न हों, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 (जो उपद्रव या संभावित खतरे के मामलों में लागू होती है) लागू थी और उन्हें जल्दी से तितर-बितर हो जाना चाहिए था, लेकिन भीड़ नरम

पड़ने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गई। भीड़ ने नारेबाजी तेज कर दी और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने और भीड़ द्वारा बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर सीधे हमले को लेकर नेटिजन्स के एक वर्ग में गुस्सा देखा गया। एफआईआर में कहा गया कि एक प्रदर्शनकारी ने लाउडस्पीकर छीन लिया और उसे तोड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को रोका और उन पर हमला किया, बल्कि लाउडस्पीकर-बैरिकेड्स भी तोड़े और पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला किया। इस हमले में एसएचओ सहित, कुछ पुलिसकर्मियों घायल हो गए और बाद में उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अतिरिक्त बल बुलाए जाने के बाद ही हिंसक प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया और धार्मिक ढांचे के आसपास की अवैध संरचनाओं को गिरा दिया गया। एफआईआर में नामजद पांच आरोपियों की पहचान मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अदनाब और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। ये सभी चांदनी मसल इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

जयपुर का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रहा

जयपुर, 08 जनवरी। राजस्थान में शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है और पिछले 24 घंटों में 2.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सीकर सबसे सर्द स्थान रहा, जबकि सुबह कुछ स्थानों

- अगले 2-3 दिन सर्दी और बढ़ने की संभावना।**

पर घने से अति घना कोहरा छाया रहा। वहीं आगामी दो-तीन दिनों में सर्दी के और बढ़ ने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में इस दौरान जैसलमेर भी 3.3 डिग्री सेल्सियस के साथ काफी ठंडा स्थान रहा जबकि राजधानी जयपुर में 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

पर्वतीय स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

विभाग के अनुसार, आगामी दो तीन दिन में उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में न्यूनतमतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने एवं तापमान सामान्य से दो-चार डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज होने तथा शीतलहर चलने के आसार हैं।

‘ भर्ती प्रक्रिया के ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)

रहे कई अस्थायी लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल और साक्षात्कार तक पहुंचे थे। इसके बाद वे असफल हो गए थे। ऐसे में नियमावली पर एक बार चयन प्रक्रिया में शामिल होने पर उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। चर्चानित अभ्यर्थियों की ओर से यह भी कहा गया कि परीक्षा के कई विभिन्न चरण हुए थे,

जिसके हर स्तर पर मिलीभगत साबित नहीं हुई है। इसके अलावा एसओजी, महाधिवक्ता और कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट सिर्फ सिफारिश मात्र थी। एकलपैठ में याचिकाकर्ताओं ने भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय होने से पूर्व ही याचिका दायर कर दी। इसके बावजूद एक्सेलपैठ ने भर्ती को रद्द करने के संबंध में आदेश दे दिए।

अमेरिका हमेशा ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)

ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों पर वेनेज़ुएला के बदहाल तेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने और इसके घटते उत्पादन को फिर से जीवित करने के लिए दबाव बना रहा है। ऊर्जा विभाग ने कहा कि अमेरिका वेनज़ुएला के तेल क्षेत्र पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध भी हटा रहा है।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने मंगलवार शाम को कहा कि वेनेज़ुएला अपने तेल का 50 मिलियन बैरल तक अमेरिकी बिन्नरी के लिए सैंपिंग, जिसकी कीमत मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से लगभग 2.8 बिलियन डॉलर है।

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने “रूस प्रतिबंध विधेयक” को मंजूर कर दिया है, जिसे रूस के व्यापारिक सझेदारों, जैसे भारत, चीन और ब्राज़ील को रूस के तेल खरीदने के लिए दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपब्लिकन सेंनेटर लिंडसे ग्राहम हैं, जो एक प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ हैं, ने यह जानकारी दी।

यदि यह विधेयक पास होता है, तो ग्राहम-ब्लूमैंगटल प्रतिबंध विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 500 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार

माईन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, अर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायवा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आर्य मैन रोड आर्यड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत पवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्स्टीटयल एरिया, फैस प्रथम, जालोरा। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 डिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

